Title: Need to provide adequate medical facilities to rural expectant mothers under National Rural Health Mission in the country.

श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज): देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव व मातृत्व सुरक्षा की देखभाल के संबंध में मंत्रालय ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एक अध्ययन कराया है। अध्ययनकर्ताओं ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा उपरांत जो रिपोर्ट दी है उसमें ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में तैनात ए.एन.एम. और डेढ़ लाख स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की सच्चाई का खुलासा है। इस संबंध में यूनिसेफ ने भी कहा है कि प्रसव हेतु न्यूनतम स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट (एसबीए) नियुक्त होने चाहिए।

यही कारण है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 52 हजार करोड़ रूपए खर्च करने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव व मातृत्व सुरक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवाएं अब तक कारगर नहीं हो पाई हैं। इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को अच्छी करके प्रसव के दौरान महिलाओं की मौतों में कमी लाई जा सके लेकिन इसमें सफलता हाथ नहीं लगी है।

स्वास्थ्य केन्द्रों की दुर्दशा, अध्ययनकर्ताओं के आंकड़ें, खुद-ब-खुद बयान करते हैं। 26 फीसदी केन्द्रों में प्रसव टेबल तक नहीं हैं, 71 फीसदी केन्द्रों में डिस्पोजेबल प्रसव किट नहीं है, 52 फीसदी ए.एन.एम. की ड्रग किट खाली हैं, 33 फीसदी केन्द्रों में चिकित्सकीय उपकरण नहीं हैं। प्रसव सिर्फ 21 फीसदी उपकेन्द्र पर होते हैं।

मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक बनाने हेतु अविलम्ब अध्ययनकर्ताओं द्वारा दर्शाई गई कमियों का समाधान करें, जिससे ग्रामीण महिलाओं को उचित स्वास्थ्य लाभ मिल सके।